International Journal of Home Science 2022; 8(2): 171-175

International Journal of Home Science

ISSN: 2395-7476
IJHS 2022; 8(2): 171-175
© 2022 IJHS
www.homesciencejournal.com
Received: 12-07-2022
Accepted: 15-08-2022

अंकिता गुप्ता
रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च सेंटर, सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
अंकिता गुप्ता
रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च सेंटर, सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

भारत में गरीबी और कुपोषण के बीच संबंध

अंकिता गुप्ता

शोध सार
यह शोध भारत में गरीबी और कुपोषण के बीच के सम्बन्ध को येतिहासिक दृष्टि से विश्लेषण करता है इस शोध में स्वतंत्र भारतीय सरकार के आर्थिक विकास और सामाजिक कार्यक्रमो के प्रभाव के द्वारा वर्तमान की स्थिति को समझने का प्रयास है।

संकेत शब्द: कुपोषण, गरीबी, भूख, उपनिवेशवाद, अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना
कुपोषण एक व्यापक शब्द है जो सभी प्रकार के हानिकारक पोषण को संदर्भित करता है। सीधे शब्दों में कहें तो कुपोषण में अल्पपोषण और अधिक पोषण दोनों शामिल हैं । WHO के अनुसार कुपोषण पोषक तत्वों के सेवन में कमी या अधिकता, आवश्यक पोषक तत्वों का असंतुलन या खराब पोषक उपयोग को संदर्भित करता है। कुपोषण के दोहरे बोझ में कुपोषण और अधिक वजन और मोटापा दोनों के साथ-साथ आहार संबंधी गैर-संचारी रोग शामिल हैं। कुपोषण चार व्यापक रूपों में प्रकट होता है: वास्टिंग, स्टंटिंग, कम वजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।

कुपोषण एक गंभीर स्थिति है और इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने आज़ादी के बाद से ही कई महत्वपूर्ण योजना चलायी है जैसे कुपोषण (एकीकृत बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना 1995, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, हाल ही में, सितंबर 2019 को 'राष्ट्रीय पोषण माह' महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कदम उठाया लेकिन आज भी इन लक्षित नीतियो के बाद भी भारत में कुपोषण उच्च बना हुआ है।

एनएफएचएस-5 ने एनएफएचएस-4 में 21 प्रतिशत की तुलना में पांच साल से कम उम्र के 19.3 प्रतिशत बच्चों में वास्टिंग (ऊंचाई के अनुसार वजन) की सूचना दी। इस क्रम में बच्चों की संभावना शहरी क्षेत्रों (18.5 प्रतिशत) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (19.5 प्रतिशत) में ज्यादा है। दुनिया भर के सभी भूखे लोगों में से 25% भारत में रहते हैं। 1990 के बाद से बच्चों के लिए कुछ प्रगति हुई है लेकिन जनसंख्या में भूख का अनुपात बढ़ गया है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 44% बच्चे कम वजन के हैं। 72% शिशुओं और 52% महिलाओं में एनीमिया है।[1] पार्टनरशिप्स एंड ऑपर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन एंड हार्मोनाइज एक्शन्स फॉर न्यूट्रीशन इन इंडिया (पोशन) के आंकड़ों के अनुमान से पता चलता है कि 309,300 बच्चे जन्म के दिन ही मर जाते हैं, और 876,200 बच्चे अपने जन्म के पहले महीने में कम वजन, और रक्त की कमी से मर जाते हैं[2]। कुपोषण और गरीबी के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। गरीबी कुपोषण की समस्या को बढ़ावा देने में योगदान देती है। गरीबी में रहने वाले लोगों को अक्सर वित्तीय सीमाओं का सामना करना पड़ता है, जो सुरक्षित पर्याप्त और पौष्टिक भोजन को ग्रहण करने में बाधा पहुँचती है[3]।

गरीबी और कुपोषण का चक्र अंतर-पीढ़ीगत है। साक्ष्य बताते हैं कि कुपोषित महिलाओं को कुपोषित बच्चे होने का अधिक खतरा होता है और यह एक अंतरपीढ़ी प्रभाव पैदा करता है। रिसर्च यह बताता है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होने वाली मौतों की कुल संख्या को 15% तक कम किया जा सकता है यदि उनके पोषण को सुधारा जाये। कुपोषण और गरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच कर रोकथाम की जा सकती है[4]।

भारत में गरीबी के चक्र को समझने के लिए हमें उपनिवेशवाद और ब्रिटिश शासन की निति के साथ स्वतंत्रता भारत की अर्थव्यवस्था को समझना आवश्यक है । १९वी सदी १८७० में दादा भाई नौरोजी के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 30 रुपये वही इंग्लैंड की 450 रुपये था। औपनिवेशिक भारत ने 19वीं शताब्दी के दौरान आर्थिक विकास देखा, जो श्रम और संसाधन गहन वस्तुओं के निर्यात, भारी निवेश के कारण था लेकिन **20**वीं शताब्दी में विकास और निवेश धीमा हो गया, जबकि उद्योगों और कुछ सेवाओं में क्षेत्र मजबूत हुए फिर भी कृषि ने अपना प्रमुख हिस्सा बनाए रखा जिसके कारण समग्र आय वृद्धि मंद रही। आजादी के दौरान भारत के आर्थिक विकास की बहस तीन प्रमुख दृष्टिकोण बॉम्बे योजना, गांधीवादी दृष्टिकोण और नेहरू दृष्टिकोण के इर्द-गिर्द घूमती रही। इन सभी में नेहरू के दृष्टिकोण को लगभग उस समय का समर्थन प्राप्त था नेहरू का दृष्टिकोण लुईस मॉडल पर आधारित था। इस मॉडल को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है जिसमे समाजवाद और पूँजीवाद दोनों विचार के अच्छे तत्वों को रखने का था[5]। यह स्पष्ट है कि भारत को एक कमजोर और समस्याग्रस्त आर्थिक संरचना विरासत में मिली है। यह कम औद्योगिक विकास और स्थिरता के साथ एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी जहा पे कृषि संबंध और पूंजी की कमी महसूस की गई । स्वतंत्र भारत की सरकार ने आज 75 सालो कई सुधारो के द्वारा इस संरचना को तोड़ने के लिए प्रयाशरत है। आज़ादी के बाद सरकार ने राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियों को बनाते समय कृषि संरचना की मूलभूत सामाजिक और आर्थिक समस्याएं को देखते हुए 1950 के दशक में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) ग्रामीण उत्थान का एक व्यापक कार्यक्रम और भूमि सुधार जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्राप्ति के लिए, भारतीय राज्य ने एक विकासात्मक राज्य की भूमिका निभाई। लेकिन १९९० तक आते आते अर्थव्यवस्था अत्यधिक कमजोर हो गयी और भारत को आर्थिक सुधार करने पड़े। सुधार कार्यक्रम

एक व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण और संरचनात्मक थे । इस १९९० के प्रमुख व्यापक आर्थिक ने वैश्विक बाजार के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिक एकीकरण किया और भारत एक उच्च आर्थिक विकास पथ पर चला पड़ा और इससे राष्ट्रीय आय में यह अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । आंकड़े बताते हैं कि गरीबी तेजी से घट रही है बहु-आयामी गरीबी (एमडीपी) पर यूएनडीपी की एक रिपोर्ट (2022) बताती है कि 2005-2006 से 2019-20 की अवधि में भारत में 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले, गरीबी की घटनाओं में 55.1% से 16.4% तक तेजी से गिरावट आई है। इसमें से दो-तिहाई पहले 10 वर्षों के दौरान और एक-तिहाई अगले पांच वर्षों में निकल गए[6]।

गरीबी, भूख और कुपोषण

भारत में भूख और कुपोषण खाद्य असुरक्षा या पर्याप्त भोजन और पोषण तक पहुँचने में असमर्थता के परिणाम हैं। 2001-03 में हर पांचवां भारतीय (20 फीसदी) कुपोषित पाया गया था[7]। बच्चों में कुपोषण की स्थिति चिंता का एक बड़ा कारण है। कुपोषण सीधे तौर पर बच्चे के विकास को प्रभावित करता है जिससे उनका विकास मंद हो जाता है शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास और संक्रमण और बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण बच्चों में संज्ञानात्मक और मानसीक विकास को भी प्रभावित करता है, जिससे शैक्षिक प्राप्ति, श्रम उत्पादकता और भविष्य की आय को प्रभावित करता है । भारत में भूख और कुपोषण का लिंग से भी सम्बन्ध है। देश की आधी महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रसार और भी अधिक है। एनीमिया मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है और यह लगभग 30 प्रतिशत शिशुओं का जन्म कम वजन के होने में भी योगदान देता है[8]।

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का अनुमान है कि भारत में 194.4 मिलियन लोग (कुल जनसंख्या का लगभग 14.5%) कुपोषित हैं। 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है । इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के अनुसार, 2017 में, भारत के प्रत्येक राज्य में पांच साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु के लिए कुपोषण प्रमुख जोखिम कारक था। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2017 के अनुसार, कुपोषण भारत में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है[9]। यह हमारे समय की विडम्बना है कि देश में भूख और कुपोषण अभी भी इतना व्याप्त है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है।

2019-21 की अवधि को कवर करने वाले आधिकारिक राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NHFS) के अभी-अभी जारी **5**वें दौर का विवरण बताता है कि प्रजनन दर अब पहली बार प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। इसका तात्पर्य है कि जनसंख्या स्थिर हो गई है और दशकों से लगातार देखी जाने वाली उल्लेखनीय वृद्धि बंद हो गई है। पिछले स्तर पर जनसंख्या को बनाए रखने के लिए 2 पर शुद्ध प्रतिस्थापन दर अब 2.1 सीमा से नीचे है। यह सभी राज्यों में सच है। इस निम्न प्रजनन दर के साथ, 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या घट रही है और जनसांख्यिकीय रूप से, देश "पुराना" होता जा रहा है। 2015-16 में पिछले सर्वेक्षण की तुलना में, हाल ही में एनएफएचएस सर्वेक्षण से पता चला है कि बच्चों और महिलाओं में एनीमिया अब काफी अधिक है। 50% से अधिक बच्चे और महिलाएं (गर्भवती महिलाओं सहित) एनीमिक पाई गईं, जिनमें से अधिक बच्चे अब कमजोर और अवरुद्ध विकास का अनुभव कर रहे हैं। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा गरीबी पर पर शोध के नतीजे सामने आए हैं। 2015-16 के एनएचएफएस डेटा का उपयोग करते हुए गरीबी का इसका बहु-आयामी अध्ययन (एमपीआई) 3 समान संकेत -स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर

आधारित है। इन तीनों में से प्रत्येक के चार विशिष्ट संकेतक हैं जैसे पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, आवास, संपत्ति और बैंक खाते। इस तरह के प्रत्येक व्यक्तिगत मार्कर पर स्कोर को एकत्रित करना, यह प्रचलित राष्ट्रीय गरीबी-घटना को जनसंख्या के 25.1% पर रखता है। पहली बार, एक सरकारी एजेंसी ने कई मापदंड अपनाए हैं और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल जैसे निकायों द्वारा अनुसंधान की तर्ज पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। गरीबी के पिछले सभी अनुमान या तो पोषण सेवन या अर्जित आय पर आधारित थे, भोजन सेवन की परिभाषित मात्रा से कम लोगों के साथ या आय को गरीब माना जाता था।

पांचवें एनएचएफएस के अनुसार, 5 वर्ष से कम आयु के एनीमिक बच्चों की संख्या 59% से बढ़कर 67% हो गई है, जबकि एनीमिक महिलाओं की संख्या 53% से बढ़कर 57% हो गई है। पुरुषों में एनीमिया 23% से बढ़कर 25% हो गया। एनीमिक किशोर लड़कियों (15 से 19 वर्ष की आयु के बीच) की संख्या में 5% से 59% की वृद्धि हुई, और 15 से 49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं में यह **50%** से 52% तक मामूली रूप से बढ़ी। 20% तक की घटना को मध्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसके ऊपर कुछ भी गंभीर माना जाता है और कई स्वास्थ्य-कमजोरियां पैदा करता है। केरल को छोड़कर सभी भारतीय राज्य केरल में 39% से लेकर गुजरात में 80% तक पुरुष वयस्कों के प्रसार के साथ गंभीर श्रेणी में आते हैं। बड़े राज्यों में, पश्चिम बंगाल में एनीमिक महिलाओं की संख्या सबसे अधिक (71%) बताई गई है। दुर्भाग्य से, 2015-16 तक कुपोषण को कम करने में जो प्रगति देखी गई थी, वह अब दोनों लिंगों में एनीमिक की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ उलट गई है। यह बताया जाना चाहिए कि एनएफएचएस डेटा, हालांकि, पूरी तरह से निर्णायक नहीं है। एनीमिया आमतौर पर शरीर में लोहे के निम्न स्तर की विशेषता है। यह भी माना जाता है कि पोषण की कमी और ताजे फल और सब्जियों के अपर्याप्त सेवन के साथ-साथ बी-12 विटामिन की कमी भी होती है। सर्वेक्षण में नियोजित कुपोषण के सभी तीन संकेतक जो आम तौर पर एक साथ होते हैं- स्टंटिंग (उम्र के अनुसार कम ऊंचाई), वेस्टिंग (ऊंचाई के लिए कम वजन) और कम वजन (उम्र के लिए कम वजन) - किसी भी मामले में 2015-16 की तुलना में खराब नहीं हुए हैं। चरण 2 बताता है। दूसरी ओर, भारत में कोविड-19 से पहले सर्वेक्षण किए गए राज्यों में, कुपोषण के इन तीन संकेतकों में से एक या दो के संबंध में अलग-अलग परिणाम थे। 10 राज्यों में से 6 राज्यों में स्टंटिंग अधिक थी, 5 में अपव्यय में वृद्धि देखी गई, और 7 में कम वजन वाले बच्चों का अनुपात पहले से अधिक देखा गया। बिहार, गरीबी के उच्चतम स्तर वाला राज्य, सभी संकेतकों पर खराब हो गया है, जिसमें नाटे और कमजोर बच्चों की प्रमुख उच्च दर है। यह संख्या तमिलनाडु (चरण 2 में सर्वेक्षण) से 50% अधिक है, जिसकी गरीबी दर बिहार के 52% की तुलना में केवल 5% है। देश भर में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का हिस्सा जो नाटे, कमजोर या कम वजन वाले थे, उनमें मामूली गिरावट आई है; हालाँकि, हर तीसरा बच्चा अभी भी पुराने अल्पपोषण से पीड़ित है और हर पाँचवाँ बच्चा अत्यधिक कुपोषित है। तेलंगाना, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे बच्चों में तीव्र कुपोषण बढ़ा है, जबकि हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सुधार हुआ है। बिहार में 41% कम वजन वाले बच्चों का उच्चतम प्रसार था, जिसके बाद गुजरात में 40% के करीब थे।

किसी भी व्यक्ति के जीवन को यापन के लिए भौतिक वस्तुओं जी जरुरत होती है और ऐसी जरूरतों को प्राप्त करने के लिए 'धन' सबसे सामान्य साधन के रूप में देखा जाता है, गरीबी 'आम तौर पर आय या धन की कमी से जुड़ी होती है।गरीब वो है जो बुनियादी ज़रूरतें जैसे पर्याप्त

भोजन, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच नहीं है । संयुक्त राष्ट्र ने २००० ईस्वी में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) में दुनिया से अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन का लक्ष्य लिया है। जो गरीबी, भूख और कुपोषण के सम्बन्धो की गवाही की तरफ इसरा करता है ।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यो और संदर्भो के आधार पर हम कह सकते है की भारत में गरीबी और कुपोषण के बीच सम्बन्धो को समझने के लिए आज़ाद भारत के पूर्व की आर्थिक व्यवस्ता को भी ध्यान में रखना होगा भारत सरकार ने समय समय पर इससे निपने के लिए, ख़तम करने के लिए कार्य कर रही है पिछले १० वर्षो के आंकने ये बताते है की भारत में गरीबी और गरीबो की संख्या में कमी आयी है। सरकार गरीबी और कुपोषण की कमी को लेकर कार्य कर रही जो निरंतर जारी है।

संदर्भ सूची

1. सुबोध वर्मा "महाशक्ति? 230 मिलियन भारतीय रोजाना भूखे रहते हैं", 15 जनवरी 2012, द टाइम्स ऑफ इंडिया
2. पोषण। 2017. पृष्ठभूमि। http://iap.healthphone e.org/backg राउंड. html, 14 मई 2018 को एक्सेस किया गया
3. पेना एम, बकालाओ जे. कुपोषण और गरीबी। अन्नू रेव न्यूट्र। (2002) 22:241-53.दोई: 10.1146/annurev.nutr.22.120701.141104
4. भुट्टा जेडए, दास जेके, रिजवी ए, गैफरी एमएफ, वॉकर एन, हॉर्टन एस, एट अल। मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार के लिए साक्ष्य आधारित हस्तक्षेप: क्या किया जा सकता है और किस कीमत पर? लैंसेट। (2013) 382:452-77. doi: 10.1016/S0140-6736(13)60996-4 वोस्टर एचएच में भी देखें। गरीबी और कुपोषण के बीच की कड़ी: एक दक्षिण अफ्रीकी परिप्रेक्ष्य। हेल्थ एसए गेसोंडहाइड। (2010) 15: 1-6। डीओआई: 10.4102/एचएसएजी.1वी5आई1.435
5. नीरा चंडोके, प्रवीण प्रियदर्शी (2002), समकालीन भारत अर्थव्यवस्था, समाज, राजनीति, दिल्ली: पियर्सन, पीपी। 5-14
6. टाइम्स ऑफ इंडिया, (2022), 15 वर्षों में भारत में 415 मिलियन गरीबी से बाहर निकले: UNDP, 18 अक्टूबर, 2022
7. ibid, p.57 also see in UNFAO, द स्टेट ऑफ़ फ़ूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड: एराडिकेटिंग वर्ल्ड हंगर-टेकिंग स्टॉक टेन इयर्स आफ्टर वर्ल्ड फ़ूड समिट (रोम: फ़ूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस, 2006)।
8. Ibid, p. 58, also see in भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण-I: भारत 1992-93 (मुंबई: भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, 1995)।
9. https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-editorials/malnutrition-in-india-1